activity amounts to manufacture, thus attracting Central Excise Law, the turnover of such stitched covers is reported to be within the exemption limit of Rs. 30 lakhs, and therefore, these units are not required to pay central excise duty.

Sick PSUs registered in BIFR

2316. SHRI JOYANTA ROY:
DR. D. VENKATESHWAR RAO:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether out of the total 240 central public sector undertakings operating in the country 56 are sick as registered in the Board of Industrial and Financial Reconstruction;

(b) if so, whether BIFR has approved revival of 12 PSUs and winding up of six PSUs;

(c) if so, whether Government have approved the same; and

(d) the names of PSUs recommended for revival and winding up?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) and (b) The Board for Industrial and Financial Reconstruction (BIFR) has reported that as on 30.6.1996, 60 sick Central Public Sector Undertakings (CPSUs) were registered with it. BIFR has sanctioned revival schemes in respect of 13 CPSUs and has recommended 6 CPSUs for winding up to the concerned High Courts.

(c) The action in regard to individual CPSU
is to be taken by the respective CPSU in consultation with the Administrative Ministry concerned.

(d) The names of CPSUs where revival schemes have been sanctioned by the BIFR and
those recommended for winding up by the BIFR as on 30.06.1996 are given in the enclosed statement.

Statement

Names of CPSUs where revival schemes sanctioned by BIFR and those recommended for winding up by BIFR on 30-06-1996.

Name of CPSUs where revival schemes sanctioned by BIFR
1. Bharat Pumps & Compressors Ltd.
2. Triveni Structural Ltd.
3. Richardson Crudas Ltd.
4. Vignayan Industries Ltd.
5. Orissa Drug & Chemicals Ltd.
6. Tyre Corporation Ltd.
7. Bharat Brakes & Valves Ltd.
8. Braithwaite Ltd.
9. Smith Stanistreet Pharmaceuticals
10. U.P. Drugs & Pharmaceuticals Ltd
11. Bengal Chemicals & Pharmaceut Ltd.
12. Bengal Immunity Ltd.
13. Mica Trading Corpn, of India

Names of CPSUs recommended for winding up by BIFR

1. Tannery & Footwear Co. Ltd.
2. National Bicycle Corpn, of India Ltd.
3. British India Corpn. Ltd.
4. The Elgin Mills Ltd.
5. Cawnpore Textiles Ltd.
6. IISCO Ujjain Pipe & Foundry Co. Ltd.

Loans disbursed to farmers by Scheduled Banks in Orissa

2317. SHRI MAURICE KUJUR: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the total amount of loans disbursed to farmers by the scheduled banks in Orissa during each of the last two years; and

(b) the amount of loan recovered from them during the above period?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) and (b) The amount of loans disbursed to farmers by scheduled commercial banks in the State of Orissa for the years ending June 1993 and June 1994 as reported by Reserved Bank of India is as under:

(Rs. in crores)

Year ended	Disbursal to Agriculture (Amount)
June 1993	79.56
June 1994 (latest available)	169.51

The amount of loans recovered from them by the banks in Orissa during the years ending June 1993 and June 1994 is as under:—

(Rs. in crores)

Year ended	Demand	Recovery	% of Demand to Recoverv
June 1993	204.43	84.43	41.30
June 1994 (latest available)	235.66	95.21	40.40

उद्योग, कृषि, संस्कृति और शिक्षा के संबंध में कार्यक्रमों को दूरदर्शन पर प्रसारित करने के लिए समय-निर्धारण

2318. श्री अजीत जोगी: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दूरदर्शन पर कृषि, उद्योग, संस्कृति और शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों के लिए प्रतिमाह औसतन कितना समय आवंटित किया जाता है;

(ख) क्या दूरदर्शन द्वारा कृषि संबंधी कार्यक्रमों के लिए समय बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी॰ एम॰ इब्राहीम): (क) प्रमुख दूरदर्शन केन्द्रों द्वारा इन विषयों से संबंधित कार्यक्रमों का दिया गया प्रति माह अनुमानित समय निम्न प्रकार से है:-

कृषि:	11.00 घंटे
उद्योग:	1 घंटा 45 मिनट
संस्कृति:	9 घंटे 05 मिनट
शिक्षा:	136.00 घंटे

(ख) तथा (ग) सभी प्रमुख दूरदर्शन केन्द्रों द्वारा ऐसे कार्यक्रमों के प्रसारण की प्रायिकता को अप्रैल, 1994 में सप्ताह में 3/4 दिन से 5 दिन बढ़ा दिया गया था। वर्तमान में समय को और बढ़ाने की कोई योजना नहीं है।

वित्त मंत्रालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रिक्त पद

2319. श्री मूलचन्द मीणा: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वित्त मंत्रालय के अन्तर्गत आय-कर सीमा शुल्क, बैंककारी और बीमा विभागों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कुल कितने पद रिक्त हैं;

(ख) इनका श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन पिछली रिक्तियों (बैकलाग) को भरने के लिए मंत्रालय द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है और इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी॰ चिदम्बरम): (क) और (ख) ऐसे पदों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है (नीचे देखिये)।

(ग) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अनुदेशों के अनुरूप बकाया आरक्षित रिक्तियों को भरे जाने के सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

विवरण

विभागानुसार/श्रेणीनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवारों के लिए खाली पड़े पदों को कुल संख्या का ब्यौरा

	समूह क		समूह ख		समूह ग		समूह घ		कुल
	अ.जा.	अ.ज.जा	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.ज.जा.	
आयकर	शून्य	शून्य	3	3	541	491	76	41	1155
सीमा शुल्क	11	7	1	-	215	232	27	25	518
बीमा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	34	130	8	16	188

	अधिकारी		लिपिक		सब स्टाफ		
	अ.जा.	अ.ज.जा	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.ज.जा.	
बैंकिंग	84	98	503	474	241	613	2013